

158

APPLICATION FOR REVISION BEFORE REVENUE BOARD, INDORE

Application for Revision No. _____/2018

PBR/मिहानी/इंदौर/म.प्र./2018/2505
2505

1. Mrs Abha Garg W/o Mr. Anil Kumar Garg,
2. Ms Anjali Garg D/o Mr. Anil Kumar Garg, and
3. Ms Anubha Garg D/o Mr. Anil Kumar Garg

304AD, Scheme No.74C,
Vijay Nagar, INDORE-452010

..... Applicants

Vs

Dept of Revenue,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal/Indore

..... Respondent

आपके
डा.मि.सी
प्रमाणित
आपके दिनांक 3-12-2017
को इंदौर कम से प्रस्तुत

प्रमाणित
17/11/18

Dear sirs,

APPLICATION FOR REVISION U/s 50 OF LAND REVENUE CODE, 1959

Revision against

Order dtd __-3-2017 (certified copy dtd 18-4-2017) passed by Upper Commissioner, Indore Division, Indore (case no. 524/2015-16) upholding Cancellation of Diversion order dtd 27-8-2014, by the 1st appellate authority, Addl. Collector.

Subject matter

SDO Sanwer passed Diversion Order (dtd 27-8-14) for land in Vill. Arjun Baroda for use as Hotel, dismissing objections by Umesh Agrawal who claimed that by signing MOUs for sale of land, the applicants had lost right to divert the land.



Objector appealed for cancelling of this order to Addl. Collector on the ground that objector had filed civil suits for specific performance of MOUs which was allowed by order dtd 15-6-14, dismissing applicants' contention that

- diversion could not be refused on any grounds other than two grounds specified in Sec 172(2) of LRC.

- MOUs and suits for specific performance is not included in these grounds, AND

[Handwritten signature]

- subject land must be "**deemed diverted**" u/s 172(1) of LRC for being situated in a village with population below 2000, outside 5 miles of city limits.

Applicants' appeal to Upper Commissioner (No. 524/2015-16) was summarily dismissed without addressing the legal issues of Sec 172(1) and 172(2) of LRC.

Applicants had filed separate appeal to Addl Collector against the same order of SDO on the ground that assessment of premium/revenue was faulty. This appeal was rejected.

Consequently, 2nd appeal was filed before Upper Commissioner (No. **290/2015-16**) which was rejected under a single order for both the appeals (No. 290 & 524/2015-16).

Against this single order, a Revision has been filed before hon'ble Revenue Board (No. **R-1875-PBR/17**) based on legal advice to the applicants.

However, only to guard against technicality, this Revision is also being submitted.



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/2505

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-6-2018	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के आदेश दिनांक 3/2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17-4-18 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश की सत्यप्रतिलिपि आवेदकगण को दिनांक 18-4-17 को प्राप्त हो चुकी थी, उसके बाद भी आवेदकगण द्वारा विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में बताये गये आधार समाधान कारक नहीं है । आवेदक द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । अतः विलम्ब का कारण सद्भाविक नहीं होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरुद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-</p> <p>"धारा 5 - व्याप्ति - अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>